असिंचित भूमियों की उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इन विकसित की गई प्रौद्योगिकियों में ये शामिल हैं (i) लवण प्रभावित भूमियों के सुधार के लिये प्रौद्योगिकी (ii) विभिन्न भूमि क्षमता एककों के तहत आने वाली भूमियों की उत्पादकता में सुधार के लिए संरक्षित खेती तथा (iii) बारानी भूमियों के लिए एकल बारानी प्रौद्योगिकी।

(ग) से (च) विभिन्न राज्य सरकारों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि विस्तार प्रणाली से मुख्यतः ९ संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। किसान खेतों, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाएं तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान इन प्रौद्योगिकियों के प्रथम स्तर का प्रदर्शन करता है। ये संस्थान नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों के बारे में विस्तार कार्मिकों को भी प्रशिक्षित करते हैं।

किसानों को जानकारी देने के लिए भूमि संरक्षण, प्रबन्ध तथा सुधार से संबंधित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा पूरे देश में उपरोक्त कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश में आवश्यकता पर आधारित मृदा संरक्षण उपायों को अमल में लाया जा रहा है। भारत सरकार ने भी 500—1125 मि. मी. के बीच वर्षा वाले तथा 30% से कम सिंचाई वाले 16 राज्यों के 99 जिलों में जुलाई, 1986 से बारानी कृषि के लिए एक राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम शुरू किया था। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में भूमि सुधार तथा विकास निगमों की स्थापना की गई है। करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षारीय भूमिदों का सुधार किया गया है तथा उनमें फसलें उगाई जा रही हैं।

Short term loans to States for kharif seasons

1341. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government had issued short term loans to States for the purchase and distribution of agricultural inputs during the kharif season;

(b) if so, the loans issued and the amount distributed among the States;

(c) the amount provided to Madhya Pradesh for the said purpose; and

(d) to what extent it has helped the farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) A statement indicating the amount of short-term loans sanctioned to States for Kharif, 89 season is attached. (*See* below)

(c) An amount of Rs. 7.75 crores has been provided to Madhya Pradesh as short-term loan for Kharif, 1989 season.

(d) The short term loan sanctioned to States is to be utilised by institutional agencies mainly for timely purchase and distribution of agricultural inputs. Which thus helps farmers.

Statement

Short-Term Loan sanctioned to States during kharif 1989 season

Sl. No	Name of State	(Rs. Crores Amount)
1	Andhra Pradesh	12.50
2	Karnataka	9.40
3	Kerala	2.65
4	Tamil Nadu	5.85
5	Gujarat	5.20
6	Madhya Pradesh	7.75
7	Maharashtra	11.15
8	Rajasthan	5.75
9	Haryana	3.40
10	Punjab	7.90
11	Uttar Pradesh	17.50
12	Himachal Pradesh	0.80
13	Assam	0.95
14	Bihar	17.10
15	Orissa	8.25
16	West Bengal	13.60
17	Tripura	0.35
18	Manipur	0.55
19	Meghalaya	0.10
20	Sikkim	0.10
	TOTAL :	130.85

Central assistance to Punjab under the integrated development of small and medium towns

1342. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the amount of Central assistance provided to the State of Punjab during the last three years, respectively under the scheme for integrated developent of small and medium towns; and

(b) the names of such towns where the amount allocated has been fully utilised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Central assistance released under the Scheme of Integrated